भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1675**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आसियान देशों के साथ सहयोग

1675. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एसोसिएशन (आसियान) के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव तैयार किया है और वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के बाद नियम आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण का भी आह्वान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करने की भी घोषणा की है और आसियान भागीदारों के साथ नई दिल्ली के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्टैक को साझा करने की पेशकश की है तथा इस प्रस्ताव में आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण और गलत साइबर सूचना के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई करने और बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को उठाने का आह्वान शामिल था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?,

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हाँ। 20 वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है:

i. i. बहु-मोडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना जो दक्षिण पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ती है

ii. भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान भागीदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई

iii. डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत फंड की घोषणा की

iv. हमारी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) को समर्थन के नवीनीकरण की घोषणा की गई।

v. बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया

vi. भारत में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित किया

vii. मिशन लाइफ पर मिलकर काम करने का आह्वान किया

viii. जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की

ix. आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण और साइबर-दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया

x. डिजस्टर-रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित किया

xi. आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया

xii. समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया

12 सूत्रीय प्रस्ताव की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। संबंधित नोडल एजेंसियों में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं।

*****